जून- 2024, वर्ष 33, अंक 59

उत्तर प्रदेश संदेश

सोलर रूफटॉप लगवाएं

पीएम सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना

योजना के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ़्त बिजली

संयंत्र की क्षमता	केंद्र सरकार का अनुदान (रु.)	राज्य सरकार का अनुदान (रु.)	कुल अनुमन्य अनुदान (रु.)
1 KW	30,000	15,000	45,000
2 KW	60,000	30,000	90,000
3 KW	78,000	30,000	1,08,000
4 KW	78,000	30,000	1,08,000
5 KW	78,000	30,000	1,08,000

- प्लांट की अनुमानित लागत ₹60,000 प्रति किलोवाट।
- सोलर पैनलों की कार्य क्षमता अवधि लगभग 25 वर्ष।
- 3 KW का प्लांट मात्र ₹1800/- की आसान ईएमआई पर लगवाएं।
- मात्र 7% की ब्याज दर पर बैंक लोन।
- सोलर प्लांट कमीशनिंग के उपरांत सब्सिडी डी.बी.टी. द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में।
- बिजली बिल में दो तिहाई तक की बचत।
- यूपीनेडा में पंजीकृत वेंडर के माध्यम से ही सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं। वेंडर का चयन ध्यानपूर्वक करें।

योजना का लाभ उठाने के लिए शीघ्र आवेदन करें -

https://pmsuryaghar.gov.in/

किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के लिए वेबसाइट
https://upnedasolarsamadhan.in पर जाएं।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

जून-2024, वर्ष 33, अंक 59

उत्तर प्रदेश

संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :

संजय प्रसाद

प्रमुख सचिव, सूचना

❖

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :

शिशिर

सूचना निदेशक

❖

सम्पादकीय परामर्श :

अंशुमान राम त्रिपाठी

अपर निदेशक, सूचना

❖

डॉ. मधु ताम्बे

उपनिदेशक सूचना

❖

डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह

सहायक निदेशक, सूचना

❖

प्रभारी सम्पादक :

दिनेश कुमार गुप्ता

उपसम्पादक, सूचना

❖

अतिथि सम्पादक :

कुमकुम शर्मा

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ

ईमेल : upsandesh20@gmail.com

दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9412674759, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- जीवन में रामत्व — 3
  –ॠचा सिंह
- आर्थिक शक्तिपुंज बनता यूपी का पर्यटन उद्योग — 8
  –सियाराम पांडेय 'शांत'
- गरीबी उन्मूलन की तेज़ रफ़्तार — 12
  –अंजुम इलाही
- पशुपालन एवं डेयरी में हुए गुणात्मक सुधार — 15
  –डॉ. अजय कुमार मिश्रा
- पूर्वांचल को नवकी बीमारी से बचाने वाले बाबा — 18
  –यशोदा श्रीवास्तव
- बेरोज़गारों के लिए वरदान है एक ज़िला एक उत्पाद योजना — 21
  –रवि प्रकाश
- अमृत सरोवरों से सँवरते गाँव और खुशहाल होता प्रदेश — 25
  –प्रेमशंकर अवस्थी
- विकास के लिए महिला सशक्तीकरण ज़रूरी — 29
  –रंजना मिश्रा

सम्पादकीय

माता भूमिः पुत्रोडहं पृथिव्याः अर्थात धरती माता और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, ''पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध हमारे जीवन, हमारी सृष्टि से है। स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण सभी प्राणियों के जीवन को सुगम बनाता है।'' पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर चंदन का पौधा लगाकर अपने दिन की शुरुआत की तथा अन्य सभी लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। उन्होंने अपने कर्मस्थल साधना स्थल गोरखपुर में हरिशंकरी का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पीपल, पाकड़ बरगद के पौधों को संयुक्त रूप से लगाने को हरिशंकरी कहा जाता है, इन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश का स्वरूप माना जाता है। ये अन्य पौधों की तुलना में सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं। यह अत्यन्त सौभाग्य की बात है कि पाँच जून को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिन भी होता है जिसे वे प्रतिवर्ष प्रकृति के सान्निध्य में व्यतीत कर मनाते हैं। एक कर्मयोगी के रूप में उनकी छवि अभूतपूर्व है। भारतीय संस्कृति, संस्कार व पारमार्थिक संवेदनाओं के कुशल संरक्षण की उनकी भूमिका अतुलनीय है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहे प्रदूषण पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि, ''प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अपने स्तर पर गम्भीर प्रयास कर रही है पर इसके साथ ही प्रदूषण के घातक दुष्परिणामों से बचने के लिए हर व्यक्ति को पर्यावरण के अनुकूल आचरण अनिवार्य रूप से करना होगा।'' उन्होंने बताया कि पर्यावरण पृथ्वी जल, वायु तथा पेड़ पौधों का समन्वित रूप है। हमारी देह भी पंचतत्व से ही बनी है। अतः इन पांच तत्वों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इन्हें प्रदूषण से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि, हम सभी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। उन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ को घातक बताते हुये इसके संरक्षण की बात की। मुख्यमंत्री जी का प्रकृति से लगाव ही उनमें कुशल नेतृत्व की क्षमता विकसित करता है। उनके व्यक्तित्व को करीब से समझने पर पता चलता है कि वे वस्तुतः प्राणिमात्र से प्रेम करते हैं यही वजह है कि उनके निर्णय अपने आप में जनहित और जल कल्याण के लिए होते हैं।

सम्पादक

जीवन में रामत्व

—ऋचा सिंह

श्रीराम को सनातन धर्म में विष्णु का अवतार माना गया है। लोग उनको भगवान और आराध्य मान कर पूजार्चन करते हैं। लेकिन जब हम राम के सम्पूर्ण जीवन का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि राम केवल पूजा के विषय नहीं हैं वह अनुकरणीय हैं हर स्थिति काल में जीवन को दिशा प्रदान करने वाले प्रेरणा पुंज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राम ने स्वयं को एक राजा और भगवान के अवतार के रूप में नहीं अपितु जननायक के रूप में स्थापित किया। हम उनके संपूर्ण जीवन में देखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन स्थितियों में भी मर्यादा के नूतन आयाम स्थापित किए। राजकुल में जन्म लेने के बाद भी श्री राम ने अपना जीवन राजसी वैभव में नहीं बिताया। उनका बाल्यकाल आश्रम में व्यतीत हुआ, गुरुकुल में वह राजकुमारों की भांति नहीं अपितु सामान्य बालकों की भांति अपने और आश्रम के सारे कार्य करते थे। जब वह युवा हुए और राज्याभिषेक का समय आया तो उन्हें पिता के वचन के लिए वनगमन करना पड़ा। राम का जीवन मानवीय संबंधों के मार्गदर्शन में प्रेरणा देता आया है जिसके कारण वह लोक चेतना और परम्परा में सदैव जीवंत रहते हैं। जो लोक में व्याप्त है वह कालजयी है, वही सर्वमान्य है, वही अनुकरणीय है, वही वंदनीय है।

लोक परंपरा में भी हम पाते हैं कि जन्मोत्सव, विवाह, हवन, कीर्तन, मांगलिक आयोजन आदि में महिलाएं जो मंगल गीत गाती हैं उसमें भी राम का नाम और उनका संबंध मूल्य ही समाहित है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो लोक के मन में हैं जो जन–जन के हृदय में बसते हैं। देखें तो राम ही त्यौहार हैं, उल्लास हैं उत्सव हैं, भक्ति हैं, शक्ति हैं, पूजा हैं, ज्ञान हैं, प्रेरणा हैं और जीवन के प्रकाश स्तम्भ हैं। लोक गीत, संगीत, संताप सब कुछ राम ही हैं। लोग उन्हीं के गीत गाते हैं और अपने दुःख को अपने पीड़ा को संताप को उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं को अर्पित करते हुए स्वयं के जीवन को राममय बना लेते हैं। राम केवल जन–जन की भावना नहीं या सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भगवान राम तो जीवन जीने का तरीका है। फिर चाहे वह संबंध मूल्यों को निभाना हो धर्म के मार्ग पर चलना हो या

फिर अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के साथ कर्त्तव्य निर्वहन हो। राम सिर्फ कहने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है बल्कि हर मायने में वह एक उत्तम और आदर्श पुरुष हैं वह जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाले प्रकाश स्तम्भ हैं। राम के जीवन आदर्शों को अनुकूल स्थिति में अपने आचरण में लाना जीवन को सरल और सहज बनाता है। श्री राम का जीवन आदर्श, नैतिकता और व्यवहार का उच्चतम मापदंड है जो हर स्थिति में प्रासंगिक हैं। गुरु–शिष्य, राजा–प्रजा, स्वामी–सेवक, पिता–पुत्र, पति–पत्नी, भाई–भाई, मित्र–मित्र के आदर्शों के साथ धर्म नीति राजनीतिक, अर्थनीति के साथ सत्य, त्याग, सेवा, प्रेम, क्षमा, परोपकार, शौर्य, दान आदि मूल्यों का सुंदर, समन्वित आदर्श रूप राम के संपूर्ण जीवन में समय–समय पर देखने को मिलता है। श्री राम के जीवन के पुरुषोत्तम होने की विशेषताओं का संदर्भ रामायण में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है जिसका जीवन में अनुकरण करने पर समरसता पूर्ण समन्वित और खुशहाल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। श्रीराम का जीवन इतना अदभुत और विशाल है कि उनके जीवन के प्रसंगों को बार–बार देखने और सुनने से भी मन नहीं भरता।

लोक परंपरा में भी हम पाते हैं कि जन्मोत्सव, विवाह, हवन, कीर्तन, मांगलिक आयोजन आदि में महिलाएं जो मंगल गीत गाती हैं उसमें भी राम का नाम और उनका संबंध मूल्य ही समाहित है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो लोक के मन में हैं जो जन–जन के हृदय में बसते हैं। देखें तो राम ही त्यौहार हैं, उल्लास हैं उत्सव हैं, भक्ति हैं, शक्ति हैं, पूजा हैं, ज्ञान हैं, प्रेरणा हैं और जीवन के प्रकाश स्तम्भ हैं। लोक गीत, संगीत, संताप सब कुछ राम ही हैं।

आज ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ने कितनी भी प्रगति कर ली हो लेकिन जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर पाता है तब वह श्रीराम के आदर्शों में ही समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। राम तो प्रभु का अवतार थे लेकिन जब उन्होंने भी मानव शरीर में धरती पर जन्म लिया तब उन्हें भी सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन राम ने हर स्थिति में स्थितिप्रज्ञ होकर कभी मर्यादा का उलंघन नहीं

किया उनके जीवन में यह विशेष और अनुकरणीय है। श्री राम का जीवन हर मानव के हृदय में मन मस्तिष्क में इसलिए बसा हुआ है क्योंकि उनकी कथाएं लोक में व्याप्त हैं। हजारों वर्षों से राम कथा का जतन एवं संवर्धन कलाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, मंचन के माध्यम से आम जनमानस के बीच होता रहा है। देखा जाए तो लोक संस्कृति के विभिन्न प्रकारों में रामायण प्रदर्शित होता है जिसमें अपनी भिन्न–भिन्न परंपराएं अपनी विशिष्ठ वेशभूषा, भाषा के साथ जन जीवन के कई आयाम देखने को मिलते हैं। जिससे जनमानस अपने आप को समृद्ध करता रहता है। लोकमंगल की भावना में भी राम के जीवन की अनंत कहानियों द्वारा बच्चों में मूल्यों को रोपित करने की परम्परा चली आ रही हैं। राम के नाम के सहारे अनंत गीतों, कहानियों, मनोभावों की जनमानस भावाभिव्यक्ति करता आया है। राम केवल लोगों की भावनाओं में समाए हुए देव नहीं है जिनके प्रति सिर्फ आस्था रखी जाए बल्कि राम सही मायने में मर्यादा पुरुषोत्तम है जो जीवन जीने का तरीका है। राम का चरित्र, आदर्श, धर्म पालन, नैतिकता और मानवीय संबंधों के मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करता आया है। क्योंकि जनजीवन हर आयाम में हर कलाओं में राम के जीवन को उनके आदर्शों को प्रकट करता रहा है। हम देखे तो राम का जीवन ही ऐसा है जो जनमानस से रिश्ता जोड़कर रखता है।

श्रीराम के लिए समाज के सभी वर्ग समान थे, उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था जैसा हम उनके जीवन में पाते हैं कि निषाद राज, केवट और शबरी माता, जटायु बानर सेना इसके उदाहरण हैं। उनके राज्य में सभी वर्गों में समानता और समान अवसर प्राप्त थे सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। राम ने समाज के प्रत्येक वर्ग को आपस में जोड़कर रखने का संदेश दिया उन्होंने प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया।

श्रीराम के लिए समाज के सभी वर्ग समान थे, उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था जैसा हम उनके जीवन में पाते हैं कि निषाद राज, केवट और शबरी माता, जटायु बानर सेना इसके उदाहरण हैं। उनके राज्य में सभी वर्गों में समानता और समान अवसर प्राप्त थे सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। राम ने समाज के प्रत्येक वर्ग को आपस में जोड़कर रखने का संदेश दिया उन्होंने प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया। माता शबरी में भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम और भक्ति भाव देखने को मिलता है जो अपने प्रभु राम के लिए चख कर मीठे बेर एकत्र करती थीं इस आस में कि भक्ति और प्रेम के भूखे उनके राजा राम एक दिन उनकी कुटिया में अवश्य आयेंगे। राम प्रेम के जूठे बेर ग्रहण कर ऐसे नैतिकता के संदेश प्रेषित करते हैं जो लोक चेतना में आज भी जीवंत होकर व्यक्ति को नर से नारायण बनने की सीख देते हैं।

श्रीराम का जीवन सामाजिक चेतना, समृद्धि, सद्गुण और सहानुभूति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा स्रोत है। राम को पिता के वचन के लिए वैभवशाली जीवन त्याग करने में एक क्षण भी नहीं लगा। आज के युग में अपने छोटे से अधिकार को लोग त्यागना नहीं चाहते लेकिन श्रीराम ने समाज, परिवार में पुत्र और भाई के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया। राज्य छोटे भाई को सौंप कर राम ने भरत से न ही कभी ईर्ष्या की ओर न ही द्वेष बल्कि हमेशा भरत के प्रति प्रेम रखा और उन्हें राज संभालने के लिए प्रेरणा देते रहे। राम का व्यक्तित्व इतना विराट था कि उनमें संपूर्ण प्राणियों के लिए स्नेह और सम्मान का भाव था। श्री राम मनुष्य से ही नहीं पशु, पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी स्नेह और लगाव रखते थे। कुछ प्रसंगों द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि माता सीता का हरण होने के बाद श्री राम पशु पक्षियों और प्रकृति से भी संवाद कर रहे हैं और माता सीता के बारे में पूछ रहे हैं, राम सेतु निर्माण में गिलहरी से संबंधित एक अत्यंत रोचक प्रसंग है, ऐसे अनगिनत प्रसंग हमें श्री राम के जीवन से जुड़े हुए दिखाई और सुनाई पड़ते जो समरसता, स्नेह और प्रेम के पर्याय हैं।

राम का जीवन मानवीय संबंधों के मार्गदर्शन में प्रेरणा देता आया है जिसके कारण वह लोक चेतना और परम्परा में सदैव जीवंत रहते हैं। जो लोक में व्याप्त है वह कालजयी है, वही सर्वमान्य है, वही अनुकरणीय है, वही वंदनीय है। लोक परंपरा में भी हम पाते हैं कि जन्मोत्सव, विवाह, हवन, कीर्तन, मांगलिक अयोजन आदि में महिलाएं जो मंगल गीत गाती हैं उसमें भी राम का नाम और उनका संबंध मूल्य ही समाहित है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो लोक के मन में हैं जो जन–जन के हृदय में बसते हैं। देखें तो राम ही त्यौहार हैं, उल्लास हैं उत्सव हैं, भक्ती हैं, शक्ति हैं, पूजा हैं, ज्ञान हैं, प्रेरणा हैं और जीवन के प्रकाश स्तम्भ हैं।

श्रीराम लोकनायक थे बानरो की छोटी सी सेना पर अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की जो असत्य पर सत्य की जीत का राम के जीवन से मानव जाति को सबसे बड़ा संदेश है। लंका विजय के बाद राम ने कहा–

अपि स्वर्णमयी लंका न में
लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि
गरीयसी।।

अर्थात लंका स्वर्ण से निर्मित है, फिर भी मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है।

राज कुल में पैदा होने के बाद भी राम ने कभी राजसी वैभव का सुख भोग नहीं किया वनवास की समय अवधि में अनेक कष्टों का सामना किया। वह चाहते तो चक्रवर्ती राजा की तरह स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे परंतु उन्होंने लोकनायक के रूप में आदर्श स्थापित किया। उनके राज्य में सबको अपनी बात कहने का अधिकार था। जब धोबी ने माता सीता पर प्रश्न चिन्ह लगाया और माता सीता एक बार पुनः वनवास के लिए प्रस्थान कर गईं तब श्री राम ने भी राजसी जीवन त्याग दिया और एक वनवासी की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। एक राजा के रूप में भी श्री राम ने स्वयं को लोकनायक ही सिद्ध किया और उसी रूप में प्रजा की देखभाल की और उनके मनोभाव अनुसार कार्य किया। वर्तमान पीढ़ी और बच्चों को सीख

लेनी चाहिए कि हमें स्वयं के जीवन में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने के लिए नियम, धैर्य और अनुशासन के सद्मार्ग का चयन करना चहिए है। आज युवाओं और बच्चों में धैर्य की कमी है, क्षणिक परिवर्तन से वह चिंता में आ जाते हैं, मनवांछित कार्य न होने पर कुंठा और तनाव का शिकार हो जाते हैं यदि हम श्री राम के जीवन से सीखें तो हम पाएंगे कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और जब–पिता के वचन के लिए उन्हें वनवास जाना पड़ा उस स्थिति में भी वह स्थितिप्रज्ञ रहे। इससे आज की पीढ़ी को सीख लेना चाहिए कि कैसे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करें।

आज बहुत सारी सामाजिक, नैतिक, मानसिक समस्याओं से युवा और बच्चे भी ग्रसित हैं ऐसे में आवश्यकता है कि वह राम के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। आज जहां सभी अपना क्षेत्रीय विस्तार करना चाहते हैं, पिता–पुत्र, भाई–भाई में संपत्ति को लेकर बंटवारे हो रहे हैं, आपसी तनाव बढ़ रहे हैं वहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को देखते हैं जहां राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को राजा बना कर राज लौटा देते हैं हम ऐसी भारत भूमि का हिस्सा हैं। राम का जीवन आम जनमानस के समक्ष ऐसे आदर्श के संदेश और उदाहरण से भरा हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि राम सिर्फ पूजनीय ही नहीं, जीवन में हमें रामत्व को धारण करते हुए धर्म के पथ का अनुगामी बनाते हैं। धर्म वही है जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए उचित अनुचित का ध्यान रखकर अपने कर्तव्यों का मर्यादा के साथ निर्वहन करें जिसका राम ने अपने संपूर्ण जीवन में निर्वाह किया।

आज 500 वर्षों बाद रामलला भव्य, दिव्य, नव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं ऐसे में हर व्यक्ति जो राम में आस्था रखता है और जिसके राम प्रेरणा के प्रतीक हैं उसे अपने जीवन में रामराज की परिकल्पना और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन आदर्शों का पालन करना चहिए। रामराज की स्थापना से आशय किसी धर्म, जाति या फिर विशेष समुदाय के राज करने से नहीं है बल्कि इसका आशय सबको एक सूत्र में पिरोकर ऐसे राज की स्थापना करना है जहां हर और प्रेम, शांति, सुख सुख, भाईचारा स्थापित हो। श्री राम को भगवान के रूप में पूजते हुए यदि हम उनके आदर्शों को जीवन में उतार लें तो सही मायने में जीवन जीने का तरीका सीखा जा सकता है क्योंकि श्री राम जहां संबंध मूल्य और आदर्श के पर्याय थे वही वह वचन निभाने धर्म पालन करने से लेकर शत्रु से भी सीखने का भाव रखने वाले जात–पाँत से ऊपर उठकर समाज को सीख देने वाले उत्तम पुरुष थे।

बच्चों को राम के जीवन से राम के आदर्शों से प्रेरणा दें जिससे वो भारतीय होने पर गर्व कर सकें और विश्व बंधुत्व का भाव रखकर अपने जीवन में रामत्व के मानवीय गुणों को धारण करें। रामत्व की प्राणप्रतिष्ठा अपने मन रूपी मंदिर और जीवन में करें साथ ही राम के जीवन मूल्यों को स्वयं के जीवन में जीकर प्रमाणित करें, यही जीवन में रामत्व के भाव की प्रमाणिकता होगी। ◆

मो. : 8737879848

आर्थिक शक्तिपुंज बनता यूपी का पर्यटन उद्योग

–सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्ज़ा तो वर्ष 2016 में ही मिल गया था। हालांकि पर्यटन नीति बनने के 18 साल बाद ऐसा हो सका। वैसे भी जब पहली पर्यटन नीति बनी थी तब उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश के ही हिस्सा था। वर्ष 2001 में वह अलग राज्य बन गया था। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा उसके हाथ से फिसल गई थी। देवात्मा हिमालय की वादियों की कमी उत्तरप्रदेश को हमेशा खलती है लेकिन अभी भी उसके पास विंध्य पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन और ऐतिहासिक किलों की समृद्ध विरासत है। एक से बढ़कर एक धरोहर हैं,जिनका ढंग इतिहास–भूगोल खंगाला जा रहा है। पर्यटकों और निवेशकों को समान भाव से आकर्षित करने की दिशा में राज्य सरकार मुकम्मल प्रयास कर रही है और बहुत हद तक इसका असर दिख भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल (डीटीसीपीसी) के गठन के बाद निवेशकों की समस्याओं का समाधान द्रुत गति से हो रहा है। पर्यटन नीति 2018 के तहत 2209 करोड़ के निवेश को कमोवेश इसी रूप में देखा जा रहा है। इस निवेश का प्रभाव यह रहा है कि राज्य के 80 हजार के अधिक लोग इस क्षेत्र में रोज़गार पा सके।

से प्रचार–प्रसार भर हो जाए तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को चार चांद लग सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन का योगदान लगभग 12 प्रतिशत का है। इसे और बढ़ाने के लिए एक जिला–एक उत्पाद योजना की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में पौराणिक व पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। उसका

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से देखें तो अयोध्या, वाराणसी, आगरा और मथुरा–वृंदावन जैसे स्थानों का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। हज़ारों–लाखों की तादाद में प्रतिदिन पर्यटक इन स्थानों का भ्रमण करते हैं। योगी सरकार ने प्रत्येक जिले को पर्यटन का केंद्र बनाने की अगर योजना बनाई है तो इसके पीछे उनकी सोच प्रदेश को उत्सव भूमि के रूप में परिवर्तित करने की भी है। हर जिले में

पर्यटन योग्य स्थानों या प्राचीन व आध्यात्मिक विरासत को चिन्हित कर उनका विकास किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल को ऐसा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। हर जिले में पौराणिक स्थल तलाशे जा रहे हैं। जिस किसी जिले में कोई पौराणिक स्थल नहीं है तो वहां के मेले, महोत्सव, साहित्य, खान–पान या किसी भी विख्यात चीज को प्रोत्साहित करने पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राष्ट्रीय जीडीपी में वह 9.2 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। वर्ष 2017 से अब तक इस राज्य की सकल घरेलू आय और प्रति व्यक्ति आय न केवल दोगुना से अधिक हुई है बल्कि प्रदेश तेजी से आत्मनिर्भरता की राह पर गतिशील हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देश के अन्य राज्यों को यूपी से सीखने की नसीहत दी है तो वह उचित ही है। यूपी में जिस तरह भारी निवेश हो रहा है और हर जिले को विकसित करने पर सरकार का फोकस है,उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए हाल के महीनों में 2800 करोड़ रुपये की 650 परियोजनाओं का लोकार्पण–शिलान्यास यह बताने–जताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने, धरोहरों के सम्मान, संरक्षण और संवर्द्धन के प्रति कितनी गंभीर है। काशी, अयोध्या के बाद अब सरकार का ध्यान बुंदेलखंड की प्राचीन धरोहरों को हेरिटेज बनाने की है। उसे गति देने की है। फरवरी 2024 के राज्य सरकार के बजट में जिस तरह अयोध्या के विकास के लिए 150 करोड़, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़, मथुरा–वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़, नाथ कॉरिडोर बरेली के लिए 25 करोड़, शुक्र तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़, देवीपाटन तीर्थ विकास क्षेत्र के लिए 40 करोड़ और आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसे कमोवेश इसी आलोक में देखा–समझा जा सकता है।

पर्यटकों और निवेशकों को समान भाव से आकर्षित करने की दिशा में राज्य सरकार मुकम्मल प्रयास कर रही है और बहुत हद तक इसका असर दिख भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल (डीटीसीपीसी) के गठन के बाद निवेशकों की समस्याओं का समाधान द्रुत गति से हो रहा है। पर्यटन नीति 2018 के तहत 2209 करोड़ के निवेश को कमोवेश इसी रूप में देखा जा रहा है। इस निवेश का प्रभाव यह रहा है कि राज्य के 80 हजार के अधिक लोग इस क्षेत्र में रोजगार पा सके।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर रामलला की कृपा का प्रभाव तो सरकार पहले ही देख चुकी है। अयोध्या के नए भव्य मंदिर में रामलला के विराजने के बाद मंदिर और पर्यटन से प्रदेश सरकार का खज़ाना भर गया है। इससे उसे 12290 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। यही वजह है कि सरकार मंदिरों को जन जागरण का केंद्र तो बनाना ही चाहती है, उसे अर्थव्यवस्था के बड़े स्रोत के रूप में भी विकसित करना चाहती है। कदाचित् इसीलिए हर जिले, हर स्टेशन पर टूरिस्ट फेलो रखने के निर्देश उसने पर्यटन विभाग को दिए हैं जो पर्यटकों को वहां की मुकम्मल जानकारी दे सकें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटकों के देखने के लिए यूं तो बहुत कुछ है लेकिन कुकरैल में नाइट सफारी शुरू होते ही लखनऊ को नई पहचान मिलेगी, यहां पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश के बदलाव की चर्चा अगर राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हो रही है, तो इसके पीछे उसका 'ट्रिपल सी' अर्थात कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का मंत्र ही प्रमुख है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे सनातन आस्था के मानबिंदुओं का यशगान पूरी दुनिया में होने का सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश ने नैतिक और भौतिक उन्नयन की जड़ें तलाश ली हैं।

500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्री अयोध्याधाम में भव्य–दिव्य–नव्य मंदिर में श्रीरामलला भगवान की प्राण–प्रतिष्ठा, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार, विंध्यधाम

अंतरराष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे हैं। यहां ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। यहां छह एक्सप्रेसवे चालू हैं, सात निर्माणाधीन हैं। अगले वर्ष 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ से पहले सरकार की योजना गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा करने और उसे संचालित कर देने की है। देश का पहला इनलैंड वाटर–वे और पहली रैपिड रेल के संचालन का गौरव भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है।

'नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश' आज खुद से रूबरू है। अपनी प्रतिभा, परंपरा और संभावनाओं को न केवल पहचान रहा है बल्कि सुशासन और विकास से जुड़कर अपनी आस्था, परंपरा और विरासत को सम्मान दे रहा है। साथ ही, अपनी अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2 फीसदी का योगदान कर रहा है। बीते सात वर्षों में राज्य की सकल घरेलू आय में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की मजबूत पहचान बनी है, जो दर्शाता है कि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है।

कॉरिडोर, ब्रज भूमि, नैमिषारण्य धाम, और सोरों–सूकर क्षेत्र आदि के समग्र विकास के प्रयासों ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न प्रांतों से करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रदेश में आगमन हुआ है, जिन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। परिणामतः यहां रोजगार के अवसर बढ़े हैं, खुशहाली के नए दरवाज़े खुले हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर है। यह बदलाव, नए बनते अवसर आस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज़ से बेहद अहम हैं।

उत्तर प्रदेश में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। देश का सबसे बड़ा रेल और रोड नेटवर्क यहीं है। देश में यह इकलौता प्रदेश है, जहां पांच

उत्तर प्रदेश 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दुनिया भर से 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलना न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के किसी भी राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। यह प्रदेश को निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य और भविष्य के भरोसे के रूप में व्यक्त करता है। एक वर्ष की अवधि के भीतर 10.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। इतनी बड़ी राशि का निवेश युवाओं के सपनों को साकार करने में भी सहायक होगा। हर हाथ को काम मिलेगा, हर घर खुशहाली आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानें तो उनके कार्यकाल में साढ़े छह लाख युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियां मिली

हैं। हमने चार लाख करोड़ रुपये से लेकर 40 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों की जो यात्रा तय की है, इसने प्रदेश में नवोन्मेष और स्टार्टअप संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया है। इसका परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा 'जॉब सीकर' से आगे बढ़कर जॉब क्रिएटर बन रहा है।

25 करोड़ प्रदेशवासियों के समवेत प्रयास से आज उत्तर प्रदेश, भारत के 'श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज' बनने की ओर अग्रसर है। जो स्वप्न प्रदेश ने देखे हैं, वे साकार हों, जो संकल्प हमने लिए हैं, उनकी सिद्धि हो, इसके लिए हर प्रदेशवासी को एकजुट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने और हर प्रदेशवासी के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

वह केवल रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन परिपथ, सूफी परिपथ ही विकसित कर रही हो, ऐसा भी नहीं है। 1857 ट्रेल, क्रॉफ्ट, कुजीन व कल्चर ट्रेल जैसे नूतन सर्किट भी डिजाइन कर रही है। पर्यटन नीति में संस्कृति, मनोरंजन, विरासत, हस्तशिल्प और नव निवेश को शामिल कर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने के पक्षधर हरगिज़ नहीं है। बुंदेलखंड और बौद्ध क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी बढ़कर अधिकतम 10 करोड़ करने, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण लागत माफ करने की योजना निवेशकों को अपनी ओर सहज आकृष्ट कर रही है। होटल, मनोरंजन, थीम पार्क, पर्यटन होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित करने, प्राचीन स्थलों और हवेलियों को होटल में तब्दील करने के लिए निवेशक अनुकूल पूंजी और ब्याज सब्सिडी योजना लागू कर क्षेत्र के विकास की सरकार की अवधारणा की अभिव्यक्ति हो रही। पर्यटन क्षेत्र में 2 करोड़ का निवेश करने वाले को 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी, 5 करोड़ तक निवेश करने वालों को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का लाभ देकर सरकार जहां निवेशकों का भला कर रही है, वह प्रदेश के पर्यटन विकास में मील का पत्थर भी साबित हो रही है।जिस तरह से प्रदेश में पर्यटन सुविधाएं बढ़ रही हैं। पर्यटकों की आवक बढ़ रही है, उससे इतना तो तय है कि इस प्रदेश की गगनचुम्बी तरक्की की आधारभूमि अत्यंत मजबूत हो गई है। जो प्रदेश अतिथि देवो भव की परंपरा में जीता है,उसके भाग्य के दरवाजे तो अतिथि दर्शन से ही खुल जाते हैं। ◆

मो. : 7459998968

गरीबी उन्मूलन की तेज़ रफ़्तार

–अंजुम इलाही

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया प्रदेश का अब तक के सबसे बड़े वार्षिक बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ रुपये है, जिससे साफ है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था न केवल अत्यंत मजबूत है बल्कि आत्मविश्वास के साथ वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर तक ले जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी तरह समर्पित है। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक ही कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज़ है, जिससे समग्र संकल्पनाओं को पूरा किया जाएगा। इसी भावना से प्रेरित वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने की ओर बढ़ रही है। यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण पर केन्द्रित है। धर्मस्थलों की सड़कों के निर्माण के लिए 1750 करोड़ और धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास को 4547 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट दिया गया है। इसी तरह, विकास की अन्य मदों में भी भारी बढ़ोत्तरी की गयी है, निश्चय ही इसका भरपूर लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान समय में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वह पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश इसमें एक ट्रिलियन डालर का योगदान करना चाहता है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से प्रदेश का सकल घरेलू राज्य उत्पाद दूने से अधिक हो गया है। देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश 'बीमारू' राज्य माना जाता था, लेकिन अब वह देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। प्रदेश ने ढांचागत विकास को तेज़ गति दी है और अनेक राजमार्गों, पुलों, एक्सप्रेस हाइवे आदि का जाल बिछता जा रहा है।

प्रदेश के बजट में पूंजीगत खर्च में 91335 करोड़ की वृद्धि हुई है और यह दो लाख तीन हजार 427 करोड़ हो गया है । ढांचागत विकास को गति देने के लिए कानपुर और झांसी के बीच नया औद्योगिक नगर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिष, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली में कॉरीडोर की थीम पर ढांचागत विकास का काम किया जाएगा।

बजट आवंटन पर सरसरी नज़र डालें तो स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल बजट का छः प्रतिशत खर्च किया जाएगा जो 43 हजार 406 करोड़ होगा। इसी प्रकार कृषि के लिए 89 हजार 298 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए 33 हजार 286 करोड़ तथा शिक्षा के लिए एक लाख तीन

हजार 494 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के चलते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने ढ़ांचागत विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही समाज कल्याण तथा गरीब–कल्याण पर समुचित ध्यान दिया है। समाज कल्याण विभाग को 33,286.66 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। समाज कल्याण के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय, विधवा पेंशन, आदि योजनाएं आती हैं, जिनके लिए समुचित आवंटन किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन में 29 करोड़, अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति में 370 करोड़ की वृद्धि की गई है तथा स्कूलों में बच्चों को भोजन देने की सुविधा का विस्तार किया गया है। इसी प्रकार, स्कूली बच्चों को मिलने वाली ड्रेस सुविधा का भी विस्तार किया गया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था न केवल अत्यंत मजबूत है बल्कि आत्मविश्वास के साथ वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर तक ले जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी तरह समर्पित है। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक ही कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज़ है, जिससे समग्र संकल्पनाओं को पूरा किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु 'स्टार्टअप' की तरह 'युवा उद्यमी विकास अभियान' भी शुरू किया है। इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगो को भरपूर बढ़ावा देने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि गैर–सरकारी क्षेत्र में एमएसएमई सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को रोज़गार देता है तथा इसमें उच्च–कौशल के बजाय सामान्य कौशल वाले युवा काम कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों के लिए उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे। 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य हर साल एक लाख इकाइयों को वित्त पोषित कर अगले दस साल में एक मिलियन इकाइयों को सीधे लाभान्वित करना है।

सरकार ने पहले ही समाज के गरीब तबके के नौजवानों के कौशल संवर्धन की अनेक योजनाएं चला रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' इनमें प्रमुख है। इसके साथ ही योगी

आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई 'एक जिला एक उत्पाद योजना' ने प्रदेश के निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है जिसका अनुसरण अब देश के अनेक राज्य कर रहे हैं। प्रदेश में युवाओं के कौशल–संवर्धन के प्रयास अनेक बाधाओं के बाद अब गति पकड़ रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने युवाओं को कौशल संवर्धन के साथ ही उनकी शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। प्रदेश में तीन नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बजट में 153.60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। छात्रों को निजी उद्योगों में इंटर्नशिप कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही डाक्टरों, पैरामेडिकल व नर्सों के लिए नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बजट में अयोध्या में मेडिकल कालेज के साथ ही 1600 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के लिए बजट में लगभग 900 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। देश में अनेक उद्योगपतियों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों की शिकायत रही है कि उनको नौकरियों के लिए समुचित योग्यता और कौशल वाले नौजवान नहीं मिल पाते हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। टाटा टेक्नोलोजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के सरकारी 150 आईटीआई में आधुनिक कार्यशालाओं तथा क्लास कक्षों का निर्माण अंतिम चरण में है। उम्मीद करनी चाहिए कि इन आधुनिक सुविधाओं में पढ़े कुशल छात्र आने वाले समय में अपनी और अपने परिवार के साथ देश–प्रदेश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देंगे।

इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। जहां तक कानून–व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, योगी आदित्यनाथ की मिसाल देश भर में दी जाती है। प्रदेश में डकैती में 87 प्रतिशत, लूट में 76 प्रतिशत, हत्या में 43 प्रतिशत, बलबा में 65 प्रतिशत और फिरौती में 73 प्रतिशत की कमी आई है। जहां पिछली सरकार ने पीएसी की कई बटालियनें भंग कर दी थीं, वहीं वर्तमान सरकार ने न केवल पुलिस का बजट बढ़ाया है बल्कि पीएसी की पांच और बटालियनें बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रदेश की बेहतर होती कानून–व्यवस्था तथा पारदर्शी व बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार–मुक्त प्रशासन ने देशी–विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया है। ज़ाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असाधारण नेतृत्व में प्रदेश के विकास की मजबूत नींव पड़ रही है और वह देश–दुनिया में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नई बुलंदियां छूने जा रहा है। ◆

मो. : 9335922887

पशुपालन एवं डेयरी में हुए गुणात्मक सुधार

–डॉ. अजय कुमार मिश्रा

सामाजिक जन जागरूकता होने की वजह से लोगों का अब खान–पान रहन–सहन का स्तर पहले से न केवल बेहतर हुआ है बल्कि लोगों की समझ में भी काफी हद तक इज़ाफा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से पशुपालन और दुग्ध का महत्व प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार के लिए रहा है। पोषण और विकास के लिए लोग इसका सेवन करते रहे हैं। आधुनिक दौर में भी दुग्ध अण्डों और मांस का महत्व अत्यधिक है और गाँव शहर सभी जगह इसकी मांग अत्यधिक है। दुग्ध से निर्मित अनेक खाद्यान्न लोग नियमित रूप से प्रयोग में लाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र के विकास और दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976'' पारित कर वर्ष 1976 में एक पृथक विभाग के रूप में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना की गयी। इन्हीं नियमों के अधीन विभाग कार्यरत है जिसका सीधा उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी पहलुओं का ध्यान रखकर विकास करना है। सार्थक प्रयासों से ही यह सम्भव हो पाया है की वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है और पशुपालन निर्धारित नियमों के अधीन, सम्पूर्ण देखरेख और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ किया जा रहा है। पशुपालन विभाग का सृजन जनवरी 1944 में हुआ था।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के कुशल संचालन में विभाग में विगत वर्षों में व्यापक बदलाव और प्रभावशाली नीतिया बनायीं गयी हैं जिसका सीधा उद्देश्य पशुपालन एवं दुग्ध का विकास और विस्तार करना रहा है। यदि दुग्ध विकास विभाग की बात किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के कृषकों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गांव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यक्रम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं विसंक्रमित दूध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। सार्थक प्रयासों का ही परिणाम है कि समय के साथ–साथ विभाग अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। यदि पशुपालन की बात किया जाये तो ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान तथा रोज़गार सृजन हेतु वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन विकास, कुक्कुट विकास, रोग नियंत्रण, चारा विकास एवं पशुपालन सम्बन्धी अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिससे उन्हें संरक्षित किया जा सके।

पशुपालन एवं डेयरी में कई सुधार किये गए हैं जो जन उपयोगी हैं। विभाग लगातार कार्य कर पशुओं की निगरानी और संरक्षण प्रदान करता रहा है। पशुओं में होने वाले लम्पी रोग पर न केवल पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया

पशुपालन एवं डेयरी में कई सुधार किये गए हैं जो जन उपयोगी हैं। विभाग लगातार कार्य कर पशुओं की निगरानी और संरक्षण प्रदान करता रहा है। पशुओं में होने वाले लम्पी रोग पर न केवल पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया गया है बल्कि 08 करोड़ 87 लाख पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के पश्चात् गोवंश की सुरक्षा के लिए तेजी से कार्य हुआ है स्वयं मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर इसका संज्ञान लेकर बड़े बदलाव कर गोवंश को विशेष रूप से संरक्षित किया है।

गया है बल्कि 08 करोड़ 87 लाख पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के पश्चात् गोवंश की सुरक्षा के लिए तेज़ी से कार्य हुआ है स्वयं मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर इसका संज्ञान लेकर बड़े बदलाव कर गोवंश को विशेष रूप से संरक्षित किया है। निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु 6484 गोआश्रय स्थलों की स्थापना किया गया है जहाँ पर निराश्रित गोवंश के रहने खाने–पीने की समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है परिणाम स्वरूप 1073695 गोवंश को संरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत इच्छुक कृषक पशुपालक परिवारों को एक–एक गाय व 900 रु. प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है इस व्यवस्था के तहत कोई भी इच्छुक कृषक/पशुपालक इसका लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत अब तक इच्छुक कृषक/पशुपालक परिवारों को 165999 गोवंश सुपुर्द किये जा चुके है और यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कुक्कट विकास हेतु 30 हजार पक्षी क्षमता की 385 इकाइयां व 10 हजार पक्षी क्षमता की 355 इकाइयां क्रियाशील हैं जिसमें रु. 1109.29 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण हेतु 220 समितियों का गठन एवं 444 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। ई–कॉमर्स पोर्टल से 60,000 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं पराग मित्रों को जोड़ा गया है जिससे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत बकरी/भेड़ पालन/सूकरपालन/चारा विकास के कुल 82 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर रुपया 5099.70 लाख का निवेश किया गया है। वर्ष 2023–24 में कुल 1747 पशुमित्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रुपया 2106 करोड़ निवेश का एमओयू किया गया है जिसमे 1.23 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा। प्रदेश में कुक्कुट निति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 93 इकाइयों की स्थापना है। पशुधन बीमा के अंतर्गत 89084 पशुओं का बीमा किया गया है। वित्तीय

वर्ष 2023–24 में 18 मंडलस्तरीय शिविरों/मेलों का आयोजन कर कुल 157716 पशुओं को पंजीकृत किया गया है। प्रभावशाली नियंत्रण का ही परिणाम है की वित्तीय वर्ष 2022–23 में 362.42 लाख मी.टन, 2023–24 में 412.32 लाख मी.टन दुग्ध का उत्पादन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3628.892 लाख मिलियन, 2021–22 में 4041.168 लाख मिलियन, 2022–23 में 4558.548 लाख मिलियन और वित्तीय वर्ष 2023–24 में 54018.80 लाख अंडा उत्पादन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1037.550 हजार मी.टन, 2021–22 में 1127.600 हजार मी.टन, 2022–23 में 1191.760 हजार मी.टन और वर्ष 2023–24 में 1347.00 हजार मी.टन मांस का उत्पादन किया गया है। वर्ष दर वर्ष बढ़ती उत्पादन सरकार के सार्थक प्रयास को बयाँ कर रही है।

गोवंशों का संरक्षण, पशुओं हेतु समुचित टीकाकरण, स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धता, कुक्कट पालन और उसके विकास के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पशुधन एव दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में एक बैठक में निराश्रित गोवंश को वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता हेतु चारा नीति–2024 के अंतर्गत परती/गोचर भूमि पर हरा चारा उत्पादन को प्राथमिकता देने, प्रथमतः 20 हजार हेक्टेअर क्षेत्रफल में हरा चारा बोवाने का कार्य अभियान के रूप में 15 अगस्त तक पूर्ण कराने एवं समस्त जनपदों में भूसा, हरा चारा एवं दाना की उपलब्धता का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण कर सत्यापित कराने हेतु निर्देशन देकर बारीकी से उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। किसी भी गोआश्रय स्थल पर गोवंश भूखे न रहे का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक गोआश्रय स्थल पर ताजा पानी की व्यवस्था के साथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी करायी गई है। पशुधन की ईयर टैगिंग को अनिवार्य बनाया गया है तथा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। पशुधन को संचारी रोगों से बचाव हेतु व्यापक प्रबन्धन यथा वैक्सीन, औषधियों की पूर्ति भी की जा रही है। सरकार के प्रयास से ही यह संभव हो पाया है की दुग्ध, अंडा और मांस की जरूरतों की पूर्ति की जा रही है और इस क्षेत्र में लगे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त है। यह बिना दूरदर्शिता और कठिन परिश्रम के संभव नहीं हो पाता। ◆

मो. : 9335226715

पूर्वांचल को नवकी बीमारी से बचाने वाले बाबा

–यशोदा श्रीवास्तव

बतौर सीएम यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ का पहला ध्यान पूर्वांचल में महामारी का रूप धर चुके इंसेफलाइटिस की ओर गया। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में तीन दशकों से इस महामारी से हजारों बच्चों को असमय दम तोड़ते हुए देखते थे। उन्हें किसी मां की गोद सूनी होने तो किसी के आंख के तारे के अचानक गुम होने की पीड़ा द्रवित करती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूर्वांचल की जानलेवा महामारी को हर हाल काबू करने के संकल्प के साथ तेज़ी से काम शुरू कर दिया और पहले ही साल से इसका परिणाम

दिखाई देने लगा। हैरत है कि डॉक्टर वही, दवाएं वही और मेडिकल कॉलेज भी वही, लेकिन जो काम तब नहीं हो पा रहा था वह योगी के सीएम बनते ही होने लगा। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले इस बीमारी के पनपने की मुख्य वजह गंदगी पर ध्यान दिया।

उन्होंने गांव–गांव सफाई की जिम्मेदारी तय की उसके बाद बीमारी के इलाज हेतु मेडिकल संस्थानों की ज़िम्मेदारी तय की। अस्पतालों को दवाएं और सुविधाओं से लैस करने के साथ इस बीमारी के पनपने वाले महीने जुलाई से अक्टूबर तक पूरे स्वास्थ्य महकमे को सतर्क रहने का निर्देश दिया। नतीजा तीन दशकों तक मौत की वजह इस बीमारी पर काबू पाया जाने लगा। कहना न होगा इस बीमारी के समूल नाश होने तक मुख्यमंत्री खुद ही इसकी मॉनिटरिंग करते, जिलों के चिकित्साधिकारियों से सीधे बात करते और इस बीमारी की यथा स्थिति की रोज़–रोज़ जानकारी लेते। अब जब जिस बीमारी के अपडेट को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं अलर्ट हों तो ज़ाहिर है कि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड़ पर रहेगा ही। कहना न होगा 2017 के बाद धीरे–धीरे कम हो रही यह जानलेवा बीमारी 2024 के इस महीने तक करीब करीब खात्में की ओर है। इसीलिए मुख्यमंत्री को पूर्वांचल में नवकी बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला बाबा कहा जाने लगा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नवकी बीमारी के कहर से हर साल हजारों बच्चों की जान चली जाती थी। गंवई बोलचाल में नवकी बीमारी का मेडिकल नाम इंसेफलाइटिस है। 1984 के आसपास इस बीमारी का उदय सर्व प्रथम देवरिया जिले में हुआ था। अपने उदय के पहले ही साल इस बीमारी ने देखते–देखते सैकड़ों बच्चों को अपने आगोश में दबोच लिया और इतनी ही तेज़ी से बच्चों के असमय मरने का सिलसिला चल निकला। इस जिले के अधिकांश गांव इस बीमारी की चपेट में थे। लोग इसे महामारी भी कहते थे। गांव गांव पूजा पाठ और हवन कीर्तन शुरू हो गया लेकिन बीमारी काबू में आने के बजाय बढ़ती ही गई।

हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच आने वाली यह बीमारी पांव पसारती गई और बच्चे मरते गए। देवरिया जिले

से उत्पन्न यह बीमारी पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों तक पंहुच गई। इस बीमारी के इलाज के लिए गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को प्रमुख केंद्र नामित किया गया जहां पहले ही चरण में ढाई तीन सौ मरीजों का अलग इंसेफलाइटिस वार्ड स्थापित किया गया। इस बीमारी के बढ़ने का ग्राफ यूं था कि पूरा वार्ड मरीजों से भरा रहता लेकिन बड़ा सवाल यह था कि इलाज के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों और दवा के अभाव में भर्ती मरीजों का इलाज कितना हो पाता? ज़ाहिर है मरीज भगवान भरोसे ही रहने को विवश थे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अलावा पूर्वांचल के तमाम निजी नर्सिंग होम और झोला छाप डाक्टरों तक के यहां इस बीमारी के मरीज भर्ती होते रहे और मरते रहे। कहना न होगा कि 2017 तक इस रोग से हजारों लोग बे मौत मरते रहे। हर साल अगस्त महीने के शुरू होते ही गांव गांव में दहशत का माहौल बन जाता था। कब किस गांव, घर में यह बीमारी दस्तक दे दे और उस घर, परिवार के बच्चे की अकाल मौत हो जाय। कम से कम इन तीन महीनों तक पूर्वांचल में डर का माहौल बना रहता था।

वायरल इन्सेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। इसके कारण ब्रेन में सूजन आ जाती है जोकि कई तरह के वायरस के कारण हो सकती है। कई बार बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम के ब्रेन टिश्यूज पर अटैक करने के कारण भी ब्रेन में सूजन आ सकती है। इसके सिम्प्टम्स में हाई फीवर, सिरदर्द, तेज रोशनी से तकलीफ, गर्दन और कमर अकड़ना, उल्टी, सिर घूमना और कई सीरियस मामलों में पैरालिसिस और कोमा जैसी स्थिति भी हो सकती है और मौत भी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में इस बीमारी के होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इस बीमारी के वायरस मच्छर या किसी कीड़े मकोड़े के काटने के कारण बॉडी में फैल सकते हैं।

इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अकेले सांसद थे जो लगातार संसद में पूर्वांचल में हर साल असमय मौत के आंकड़ों के साथ इस मामले को उठाते रहे,केंद्र सरकार को जगाते रहे। योगी आदित्यनाथ के पहले पर ही 1999 में केंद्र सरकार ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को 77 करोड़ रूपए की भारी भरकम धनराशि सिर्फ इस बीमारी के इलाज और शोध के लिए आवंटित किया था लेकिन धन के सही उपयोग की जगह इसका बंदरबांट कर हज़म कर लिया गया। उस वक्त कैग की जांच में पाया गया था कि केंद्र सर द्वारा जारी इस राशि के वाजिब खर्च की जगह गैरज़रूरी मद में खर्च कर दिया गया इंसेफलाइटिस के इलाज में एक धेला नहीं खर्च किया गया।

वायरल इन्सेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहा

जाता है। इसके कारण ब्रेन में सूजन आ जाती है जोकि कई तरह के वायरस के कारण हो सकती है। कई बार बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम के ब्रेन टिश्यूज पर अटैक करने के कारण भी ब्रेन में सूजन आ सकती है। इसके सिम्प्टम्स में हाई फीवर, सिरदर्द, तेज रोशनी से तकलीफ, गर्दन और कमर अकड़ना, उल्टी, सिर घूमना और कई सीरियस मामलों में पैरालिसिस और कोमा जैसी स्थिति भी हो सकती है और मौत भी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में इस बीमारी के होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इस बीमारी के वायरस मच्छर या किसी कीड़े मकोड़े के काटने के कारण बॉडी में फैल सकते हैं। गोरखपुर मेडिकल कालेज द्वारा इस बीमारी में त्वरित व प्राथमिक उपचार में उपयोगी के लिए इम्यूग्लोबिन इंजेक्शन की खरीद ही नहीं की गई थी। जबकि स्वास्थ्य निदेशालय का यह एडवायजरी थी।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सिम्प्टम्स के आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि इसके बचाव के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन्स उपलब्ध है। हैरत है कि इस बीमारी के काबू करने के लिए वैक्सीन तक का उपयोग नहीं किया गया। यानि कि पूर्वांचल में इस बीमारी के फैलाव में जितना वातावरण और खुद की लापरवाही जिम्मेदार थी उससे कहीं ज्यादा इस पर काबू पाने वाला स्वास्थ्य महकमा भी जिम्मेदार था। तत्कालीन सरकारें तो बस स्वास्थ्य महकमे के बहकावे में आती रही और जिम्मेदार यह कहते रहे कि जिसको मरना है वह मरेगा ही! मानव जीवन को लेकर संवेदनशील मुख्यमंत्री ही इस बीमारी को लेकर चिंतित होता। यूपी और खास तौर से पूर्वांचल का संयोग है कि उसे योगी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला और हर साल असमय मौतों पर विराम लगा। ◆

मो. : 8795087975

बेरोज़गारों के लिए वरदान है

एक जिला एक उत्पाद योजना

—रवि प्रकाश

निर्यात प्रोत्साहन नीति, वस्त्रोद्योग नीति, फेरी नियमावली, खनन नीति मुख्यमंत्री योगी की ये योजनाएं न केवल रोजगार के अवसर हैं, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी ढेर सारी सहूलियतों से लैश है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही इन माध्यमों से ढेर सारे रोजगार के द्वार खोल दिए थे।योगी की इस नीति का उद्देश्य बंद पड़े पुराने उद्योगों में जान डालना तथा हर जिले के छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके पीछे योगी की मंशा कुशल बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना भी है। वे चाहते हैं कि कालेजों से पढ़ लिखकर निकले युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में वक्त जाया न करें। वे कुछ ऐसा करें जिससे खुद भी चार पैसा कमाएं और अपने साथ जोड़कर दो चार युवाओं को भी रोजगार दें।

योगी की गांव, शहर और जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक जिला एक उत्पाद

मिट्टी की कलाकारी में पूर्वांचल का कोई जोड़ नहीं है। गोरखपुर के निकट गुल्हरिया गांव की कुम्हारी कला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समझा जाता है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं भी गुल्हरिया के टेराकोटा कला से मंत्रमुग्ध थे। उन्हें लगा कि इसे लघु उद्योग का दर्जा देकर इस कला को न केवल संरक्षित किया जाय, इसे रोज़गार का जरिया भी बनाया जाय। कला बोर्ड के गठन का उद्देश्य मिट्टी कारीगरों को बेहतर मार्केट और राष्ट्रीय पहचान उपलब्ध कराना है। इसके लिए बोर्ड गांवों में मिट्टी कारीगरों को मुफ्त ज़मीन के पट्टे और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

आज जब रोजगार की बात होती है तो अमूमन लोग सरकारी नौकरियों की बात करते हैं यह जानते हुए भी कि बेरोजगारी के सापेक्ष सरकारी नौकरियां नहीं है और यह भी सच है कि केवल सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। ऐसे में हम जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोजगार के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीतियों को देखते हैं तो निश्चित ही रोज़गार की उम्मीद भरी एक नई राह नज़र आती है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, सूचना प्रोद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, सौर ऊर्जा नीति, नगर विमानन प्रोत्साहन नीति, एम एस एम ई एवं

उत्तर प्रदेश के ज़िलों का प्रमुख उत्पाद

आगरा – चमड़ा उत्पाद
फिरोजाबाद – ग्लास बैंग्लिस
मथुरा – बाथरूम फिटिंग्स
मैनपुरी – तारकशी
अलीगढ़ – लाक्स एवं हार्डवेयर
हाथरस – हींग प्रोसेसिंग
एटा – घुंघरू घंटी
कासगंज – ज़री ज़रदोजी
प्रयागराज – अमरूद फ्रूट प्रोसेसिंग
प्रतापगढ़ – आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग
कौशाम्बी – केला फ्रूट प्रोसेसिंग
आजमगढ़ – ब्लैक पॉटरी
बलिया – बिंदी तथा सिंहोरा
मऊ – पावरलूम
बरेली – ज़री वर्क
बदायुं – ज़री वर्क
पीलीभीत – बांसुरी
शाहजहांपुर – ज़री वर्क
संतकबीर नगर – पीतल के बर्तन
सिद्धार्थनगर – कालानमक चावल फूड प्रोसेसिंग
चित्रकूट – लकड़ी के खिलौने
बांदा – सजर स्टोन क्राफ्ट
महोबा – गौरा स्टोन क्राफ्ट
हमीरपुर – जूती
गोंडा – दाल फूड प्रोसेसिंग
बहराइच – गेंहू के डंठल की कलाकृतियां
बलरामपुर – दाल फूड प्रोसेसिंग
अयोध्या – गुड़ एवं जेगरी उत्पाद
बाराबंकी – स्टोल दुपट्टा
अंबेडकर नगर – पावरलूम
अमेठी – बिस्किट
सुलतानपुर – मूंज के फर्नीचर
गोरखपुर – टेराकोटा
कुशीनगर – काष्ठ कलाकृतियां
देवरिया – पलास्टिक के तोरण द्वार
महराजगंज – फर्नीचर
झांसी – साफ्ट ट्वायज़
जालौन – हैंडमेड पेपर
ललितपुर – कृष्ण की मूर्ति
कानपुर नगर – चमड़ा उद्योग
इटावा – आलू के उत्पाद
औरैया – देसी घी
फर्रुखाबाद – ब्लाक प्रिंटिंग
कन्नौज – इत्र
लखनऊ – लखनवी इंब्रायडरी
उन्नाव – जरी
रायबरेली – वुड क्राफ्ट्स
सीतापुर – दरी
लखीमपुर खीरी – टाइबल क्राफ्ट
हरदोई – डेरी उत्पाद
मेरठ – स्पोर्टस गुड्स
बागपत – हैंडलूम
गाजियाबाद – इंजीनियरिंग गुड्स
बुलंदशहर – पाटरी
गौतमबुद्धनगर – रेडीमेड गारमेंट्स
हापुड़ – होम फर्नीशिंग
मुरादाबाद – मेटल क्राफ्ट
रामपुर – पैचवर्क
बिजनौर – वुडेन आर्टवेयर

योजना पूरी दुनिया में सराही जा रही है। यूपी में लगभग सभी जिले ऐसे हैं जिनका अपना कुछ न कुछ खास उत्पाद या प्रोडक्ट है। ये सब या तो गुमनाम हैं या फिर प्रोत्साहन के अभाव में अपने गांव गिरांव तक सिमट कर रह गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ऐसे गंवई उत्पाद को नया आयाम दिया है। उन्होंने इसे गांव से निकालकर बड़े शहरों तक पहुंचाने की सुदृढ़ नीति और बाज़ार दिया है।

एक जिला एक उत्पाद मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी मानिटरिंग वे खुद करते हैं। वे स्वयं इससे जुड़ेन उद्यमियों से संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। मुख्यमंत्री के खुद इस योजना में दिलचस्पी लेने से करीब–करीब सभी जिलों के अपने ख़ास उत्पाद आज दूर दराज़ के बाजारों तक धूम मचाए हुए है। इस योजना के तहत स्थापित होने वाले नई इकाइयों के कामन फैसिलिटी सेंटर, डिजाइन स्टूडियो, टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिसप्ले आदि की सुविधाएं वरीयता क्रम के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम या यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से संबद्ध योजना से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था है। ऐसी योजना से जुड़े कुशल कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग के लिए अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत तैयार उत्पादों की मार्केटिंग प्रदेश में उपलब्ध एक्सपो मार्ट, प्रदर्शनी स्थलों तथा अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में की जा रही है।

योगी की गांव, शहर और जिले के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना पूरी दुनिया में सराही जा रही है। यूपी में लगभग सभी जिले ऐसे हैं जिनका अपना कुछ न कुछ खास उत्पाद या प्रोडक्ट है। ये सब या तो गुमनाम है या फिर प्रोत्साहन के अभाव में अपने गांव गिरांव तक सिमट कर रह गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ऐसे गंवई उत्पाद को नया आयाम दिया है। उन्होंने इसे गांव से निकालकर बड़े शहरों तक पहुंचाने की सुदृढ़ नीति और बाज़ार दिया है।

ओडीओपी योजना शुरू करने में सरकार दे रही ये सुविधाएं

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना प्रारंभ करने के लिए सरकार की ओर से तमाम सहूलियतें उपलब्ध कराई जा रही है जिसे इस योजना के शुरू करने में कोई बाधा न आ पाए। इसके लिए छः कैटेगरी बनाई गई हैं। इच्छुक लाभार्थी को कच्चा माल, वित्तीय सहायता, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग, डेवलपिंग डिस्प्ले तथा एक्जिबिशन एवं मार्केटिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी इस योजना के अंतर्गत आने वाले उद्यमी यदि पुरुष हैं तो उसे एक लाख और यदि महिला है तो उसे डेढ़ लाख तक की सब्सीडी संस्तुति करता है ताकि उद्यमी अपने कारोबार को अच्छे तरीके से बिना वित्तीय बाधा के चला सके। इस योजना के तहत उद्योग स्टार्ट करने के लिए उद्यमी को स्टांप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। स्टांप शुल्क में पूर्वांचल और बुंदेल खंड में सौ प्रतिशत की छूट है जबकि मध्यांचल और पश्चिमी क्षेत्र में क्रमशः 70 और 50 प्रतिशत तक ही छूट है।

पहली बार माटी कला बोर्ड का गठन

मिट्टी की कलाकारी में पूर्वांचल का कोई जोड़ नहीं है। गोरखपुर के निकट गुल्हरिया गांव की कुम्हारी कला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समझा जाता है

कि योगी आदित्यनाथ स्वयं भी गुल्हरिया के टेराकोटा कला से मंत्रमुग्ध थे। उन्हें लगा कि इसे लघु उद्योग का दर्ज़ा देकर इस कला को न केवल संरक्षित किया जाय, इसे रोज़गार का जरिया भी बनाया जाय। कला बोर्ड के गठन का उद्देश्य मिट्टी कारीगरों को बेहतर मार्केट और राष्ट्रीय पहचान उपलब्ध कराना है। इसके लिए बोर्ड गांवों में मिट्टी कारीगरों को मुफ्त ज़मीन के पट्टे और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। प्लास्टिक बैन होने के बाद अब कुल्हड़ उत्पाद का दायरा बढ़ रहा है जिससे लोगों को सीधे रोज़गार मिलने लगा है वहीं टेराकोटा के खिलौने की भी डिमांड पूरे भारत में है। ◆

मो. : 8303851539

अमृत सरोवरों से सँवरते गाँव और खुशहाल होता प्रदेश

–प्रेमशंकर अवस्थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक जल संकट से चिंतित होकर देश को जल संकट से बचाने के लिए एक ऐसा नायाब तरीका खोज निकाला उसी की परिणति है, देश में व्यापक अमृत सरोवरों का सृजन और जल संचय की बहती धारा।

वर्षा के जल की एक–एक अमृत बूँद सहेजने और सँवारने का मतलब है कि पानी की बरबादी को रोकना। आज लाखों अमृत सरोवर जल संचयन से भू गर्भ जल को स्वतः से उठाने की गवाही दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधान मंत्री की इस महत्वाकाँक्षी योजना को परवान चढ़ाने के लिए अमृत सरोवरों के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर और समय सीमा से एक वर्ष पूर्व ही कार्य पूर्ण करके देश में सरोवरों का इतिहास उत्तर प्रदेश के हवाले कर उपमान गढ़ दिया।

आज़ादी के अमृतकाल में सरोवरों के सृजन और जल विकास पर चर्चा के पहले सरोवरों के पौराणिक महत्व और उनके रख–रखाव पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है।

मानव जीवन की संरचना से लेकर जीवन्तता तक का सरोकार जल है। पंचभूत तत्वों में जल की अनिवार्यता है, 'जलमेव प्राणाः' से जीवन की सम्पूर्णता सृजित हो जाती है। जो आत्मा का पूरक है। जल तो प्राणियों का जीवन है। जीव, जन्तु, पशु, पक्षी और वनस्पतियों के पालन पोषण तथा संवर्धन के लिए भी अनिवार्यता है। इसीलिए वेदों में जल को जीवन कहा गया है। आयुर्वेद का 'भाव प्रकाश' तो यहाँ तक कहता हैः–

'जीवनम् जीविनाम् जीवो जगततन्मयम्'

जल प्राणियों का जीवन है और सारा संसार ही जलमय है यजुर्वेद में जल देव से कामना की गयी है कि 'हे–जलदेव! हमें इच्छित सुख देने के लिए जल कल्याणकारी हो, हमारे पीने के लिए सुखदायी हो। हमें सुख–शान्ति देते हुए 'जल प्रवाह' बने अपने समय के समाज सुधारक संत रहीमदास ने जल के दार्शनिक भाव में जीवन का मूलभूत सत्य खोजा है।

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरै मोती मानुष चून।।'

यहाँ आँख में पानी मर जाये तो आदमी समाज में निन्दा का पात्र बन जाता है। अगर मोती का पानी उतर जाये तो उसकी कोई कीमत नहीं लगती है। अगर चूने का पानी मर जाये तो पान का रंग बिगाड़ देता है। अगर आदमी अपने पानी की चिन्ता छोड़ दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है।

इस देश के रंग में पूरी तरह रंगकर ही रहीमदास जी ने 'पानी' की अन्तर्वेदना को अपने शब्दों में कहकर उद्घाटित किया कि ऐसा पानी केवल द्रव नहीं है। वह दीप्ति भी है।

प्राचीन भारत के प्रत्येक कालखण्ड में जल संचयन व जल प्रबन्धन के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में कूप इत्यादि जल संस्थानों अर्थात जलाशयों के लगभग एक दर्जन प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही 'कुचक्र' और 'अस्मचक्र' जैसी जल संचयन प्रणालियों का उल्लेख है।

जल संचयन या जल प्रबन्धन का पहला प्रमाण सिन्धु घाटी में खुदाई के दौरान मिला। सिन्धु घाटी के मोहन जोदड़ो नामक स्थल पर मिला महास्नानागार आधुनिक अमृत सरोवरों को भी बहुत पीछे छोड़ते हुए प्रतीत होता है। धौला वीरा नामक स्थल में अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गयी थी। इसी प्रकार कुँए बनाने की कला का विकास भी सैन्धव काल में हुआ था। सैन्धव सभ्यता के हर तीसरे मकान में कुँआ हुआ करता था। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था थी जो आधुनिकता के दौर में देखने को नहीं मिलती है। नन्दों के शासन काल में नहरों व जलाशयों का निर्माण हुआ था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में

ऐतिहासिक सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में करवाया गया था। मध्यकालीन भारत के दक्षिण भारतीय चोल शासकों ने जल संचयन व जल प्रबन्धन की न केवल बेहतर प्रणालियाँ विकसित कीं बल्कि उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ बनाया। चोलों के स्थानीय प्रशासन में तालाबों में रख–रखाव के लिए येरिवारियम जिसे तालाब समिति कहते थे। इसके संचालन का दायित्व समिति पर निर्भर था।

देश की आज़ादी के पूर्व हिन्दू शासकों और राजा महाराजाओं ने भी 'जल' के महत्व और उपयोगिता को गम्भीरता के साथ लेने की सार्थकता को हजारों तालाब, बावड़ी और झीलों का निर्माण करा कर अपने मानव धर्म का पालन किया। बुन्देलखंड के राजा महाराजा बहुत पहले ही समझ गये थें कि बारिश के पानी को रोककर बुन्देलखंड को सुरक्षित रखा जा सकता है। 9वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक हजारों की संख्या में तालाब बने। महोबा को आज भी तालाबों की नगरी कहा जाता है। कीरत सागर तालाब हजारों पर्यटकों का केन्द्र स्थल बना हुआ है।

अखिल ब्रह्मण्ड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने जल को 'प्राण' मानकर दो ब्रह्म सरोवर का निर्माण खुद ही कटाकर जल की अनिवार्यता को प्रतिबिम्बित किया है। एक 'ब्रह्म सरोवर' हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में और दूसरा राजस्थान के पुष्करनाथ में जो अजमेर जिले में आता है। जो सरोवर पुष्प से बना हो। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के हाथ से एक असुर युद्ध में जहाँ कमल गिरा वहाँ सरोवर बन गया। ब्रह्म सरोवर आज बड़े तीर्थों में शुमार है। यहाँ स्नान मात्र से मनुष्य को मोक्ष गति प्राप्त होती है।

ऋषियों और मुनियों ने साधना के लिए साधन के रूप में जलाशयों का निर्माण कराया था। वही जलाशय तपोभूमि पर तीर्थ के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नैमिषारण्य अट्ठासी हजार ऋषियों की तपस्थली है जहाँ शौनकादिक ऋषियों ने भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त एक चक्र से निर्मित चक्रतीर्थ कुण्ड विश्व के ध्यान पवित्र तीर्थ के रूप में आकृष्ट करता आ रहा है। वेदों और पुराणों के विधान में वहाँ स्नान व जलाभिषेक से मोक्ष गति प्राप्त होती है। ऐसी ही भारत में जलाशयों का तमाम इतिहास जल की महत्ता और पवित्रता का बखान कर रहा है।

पानी के अधिक दोहन से गिरता भूजल स्तर और गहराता जल संकट वैश्विक चिन्ता का गम्भीर विषय बना हुआ है। भारत इससे अछूता नहीं है। पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों का समूह भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है। आप सभी जान रहे हैं। जल समस्या पर केपटाउन ने दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। जहाँ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ जीवन निर्वाह व अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सीमित मात्र में पानी सरकारी नियमों के तहत दिया जा रहा है। स्नान पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

भारत की यह संवेदना रही है कि प्रधान मंत्री मोदी जी गहराते पानी संकट पर लगातार चिन्ता व्यक्त करते आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा विकसित और विकासशील देशों के वैश्विक मंचों में पिछले काफी समय से उठाते चले आ रहे हैं। यही है कि जी–20 की मेजबानी में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के साथ जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उनके एजेण्डे में रहा है।

भूजल से उत्पन्न जल संकट पर नीति आयोग की चिन्ता से चिन्तित प्रधान मंत्री मोदी जी ने भूगर्भ जल की उपलब्धता और उपभोग की मात्रा पर गम्भीरता से हुए विचार मन्थन 'मन की बात' कार्यक्रम में सकारात्मक दिखाई दिए हैं। अमृत सरोवरों का विकास उसकी परिणति है।

24 अप्रैल, 2022 से 'अमृत सरोवर मिशन' नाम से शुरू इस योजना से ग्राम पंचायतों का काया– कल्प हुआ है। अब सरोवरों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसे विकास के चरमोत्कर्ष तक ले जाने की शासन की मंशा है।

आज़ादी का यह 75वाँ अमृत महोत्सव देश की ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों के निर्माण की गौरवगाथा कह रहा है। इन अमृत सरोवरों में वर्ष के परिप्रेक्ष्य में जल की एक–एक बूँद को सहेजने और सँवारने का लक्ष्य समुद्र मंथन में देवताओं के अमृत कलश से कम नहीं है।

ग्राम पंचायतों में तेज़ी से हो रहे तालाबों का विकास और जीर्णोंद्धार वर्षा जल का संचयन, गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने, सिंचाई और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का सरल और कारगर उपाय तो है ही। पौराणिक महत्व के दर्शन के आलोक में तालाबों, बावड़ी, जलाशयों, सरोवरों, झील, कुँओं का निर्माण किसी भगवद् प्रेरणा से कम नहीं है।

मत्स्य–पुराण का दर्शन मानव कर्तव्य पथ का साक्षी और प्रेरक है।

दस कूप समावापी, दशवापी समोह्रदः।
दशह्रद समोपुत्रो दश पुत्र समोद्रुमः।।

तालाबों के सृजन में 'सहभागिता' पुराण की दृष्टि में कहा गया है, दस कुँओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र, दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, यानी जितना पुण्य दस पुत्रों को उत्पन्न करने पर होता है उतना ही पुण्य एक वृक्ष लगाने पर होता है। इसलिए व्यक्ति एक वृक्ष लगाकर बड़ा पुण्य अर्जन का भागी बन सकता है इतना ही नहीं पुराणों में गाँव को देवता की संज्ञा दी गयी है। हिन्दी साहित्य के नामचीन कवि डॉ. राम कुमार वर्मा ने अपनी काव्य रचना में ग्राम को देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया हैरू–

श्रम वैभव के बल पर करते हो, जड़ से चेतन का विकास,
दानों–दानों फूट रहे सौ सौ दानों से हरे हास।
यह है न पसीने की धारा, यह है गंगा की धवल धार।
हे ग्राम देवता नमस्कार...

श्रमसाध्य जीवन के हर प्रस्वेत को गंगा की धवलधार की मान्यता से किसानों व ग्राम वासियों के जीवन को आज के परिप्रेक्ष्य में जन सहभागी बनाकर अमृत तालाब के विकास की मुख्य धारा से संपृक्त देखा जाना आवश्यक है। जहाँ गाँव की महत्ता का उत्कर्ष देवता है।

उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ की बहु आयामी सोच ही कही जायेगी कि प्रदेश के चतुर्दिग विकास का हर परिणाम उसकी पराकाष्ठा पर जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों का नया भारत बनाने के लिए उनके पद चिह्नों पर ही चलकर उनकी महात्वाकाँक्षी योजना उत्तर प्रदेश के लिए वरदान मानते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम हो या जल संकट से निकलने के लिए अमृत सरोवरों का विकास या जीर्णोंद्धार, वृक्षारोपण कार्यक्रम हो या फिर जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर–घर नल योजना, कोई भी योजना बिना परवान चढ़े नहीं रह सकती।

यही ले लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अपने 'मन की बात' कार्यक्रम से शुरू हुई। 'अमृत सरोवर मिशन' योजना में ऐसा गतिशील हुए कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में भी देश का सिरमौर बन गया। निर्धारित 15415 तालाबों के सापेक्ष 8343 जलाशयों का विकास लक्ष्य अगस्त, 2022 में प्राप्त कर देश के विकास में उपमान गढ़कर कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहे हैं।

लोकतंत्र की प्राथमिक शाखा बनी ग्राम पंचायतों को

आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से निरन्तर शासन से दिये जा रहे विकास कार्य पंचायती राज अधिकार नियम 73वें संशोधन के बाद प्रधानों के अधिकार के पीछे मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ की ही प्रेरणा है कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें तालाबों का विकास और जीर्णोंद्धार कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार से मिल रहे नये–नये दायित्वों से उत्साहित ग्राम प्रधान अपने को विकास की मुख्य धारा में पाकर खुश हो रहे हैं। तालाबों के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानों पर ही निर्भर है।

सरोवरों और तालाबों का विकास रोजगार से शुरू होकर पर्यटन विकास तक ले जाने का लक्ष्य है। मनरेगा व पन्द्रहवें वित्त आयोग की आर्थिक मदद विकसित किये जा रहे तालाबों से जन सहभागी रोज़गार के अवसर उपलब्ध तो होंगे ही। जल संचयन और पौराणिक महत्व के वृक्षों का रोपण, पर्यावरण और जल बहाव को नियंत्रित करने में कारगर साबित हो रहे हैं। तालाबों के विकास से जल संचयन में ग्राम पंचायतों की भूमि का व उपयोगिता महत्वपूर्ण हो जाती है। जल संचयन का सिद्धान्त है कि वर्षा के पानी को स्थानीय जरूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संचित किया जाय और भूजल स्तर को अधिकतम संभव ऊँचाई तक बनाये रखा जाय। जल संचयन की पारम्परिक प्रणालियों से लोगों की घरेलू और सिंचाई सम्बन्धी जरूरतें पूरी होती रहती हैं तथा प्राक्रतिक संतुलन बना रहता है। ग्राम पंचायतें इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

प्रख्यात समाज सेवी सत्यम पाण्डेय का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केन्द्र की हर योजना को गम्भीरता से लेकर विकास की पराकाष्ठा तक ले जाने का सार्थक प्रयास करते हैं। आज अमृत सरोवरों का विकास और पर्यटन उनकी कर्मशीलता की गौरवगाथा समेटे हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। लखनऊ के नगर पंचायत मोहनलालगंज में वैसे तो बहुत से अमृत सरोवरों का विकास हुआ है। लेकिन हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार और 'राग दरबारी' के चर्चित लेखक पद्मश्री श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में निर्मित विशाल अमृत सरोवर की दिव्यता और भव्यता पर्यटन के लिए लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

वीरभूमि बुन्देलखण्ड जो सदैव प्यासा रहता रहा है, आज वहाँ जलधारा बह रही है। जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना बुन्देलखण्ड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महोबा में तालाबों की बहुश्रृंखलाएं पर्यटन के मुख्य विकास का आकर्षण के साथ रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही हैं। निजी तालाबों का विकास जल संचयन सिंचाई को बढ़ावा दे रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधान मंत्री की इस महत्वाकाँक्षी योजना का परवान चढ़ाने के लिए अमृत सरोवरों के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर और समय सीमा से एक वर्ष पूर्व ही कार्य पूर्ण करके देश में सरोवरों का इतिहास उत्तर प्रदेश के हवाले कर उपमान गढ़ दिया है। आज़ादी के अमृतकाल में सरोवरों के सृजन और जल विकास पर चर्चा के पहले सरोवरों के पौराणिक महत्व और उनके रख–रखाव पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है।

अमृत सरोवरों के विकास से उत्साहित उत्तर प्रदेश के जिलों में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी अपने यहाँ उत्पन्न भौगोलिक परिस्थितियों से जल संचयन के नये–नये तरीके खोज रहे हैं। फतेहपुर जिले को ही ले लीजिए, यहाँ विलुप्त हो चुकी नोन नदी के जीर्णोद्धार के लिए सैकड़ों ग्राम पंचायतों से जल सत्याग्रहियों के हज़ारों कदमों का नेतृत्व खुद फतेहपुर की तत्कालीन जिलाधिकारी ने किया। नोन नदी के 23 किलोमीटर की खुदाई के बाद तेजी से प्रवाहित हुए जल प्रवाह से सैकड़ों गाँवों को जीवन दान मिला है। इस भगीरथ कार्य संस्कृति से प्रभावित उत्तर प्रदेश व केन्द्र की सरकारों ने उन्हें 'जलपरी' की उपाधि से सम्मानित कर औरों के लिए प्रेरणाप्रद बनाया है। अमृत सरोवरों से उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आज मानव और प्रकृति दोनों को जीवन दान मिल रहा है। ◆

मो. : 9450403222

विकास के लिए महिला सशक्तीकरण ज़रूरी

—रंजना मिश्रा

प्राचीन काल के भारतीय समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा, वे सदा से समाज की प्रेरणा स्रोत रहीं, किंतु विदेशियों के आक्रमण के बाद हमारे देश और समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त होती रहीं, इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। उनकी शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाने लगा और उन्हें घरेलू कामकाजों के लिए ही उपयुक्त माना जाने लगा तथा उन्हें घूंघट में कैद कर दिया गया तथा विवाह पश्चात घर–गृहस्थी संभालना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। समाज में महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा और सतीप्रथा, बालविवाह जैसी अनेक कुरीतियों ने भारत में महिलाओं का जीवन अत्यंत दुरूह बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाएं धीरे–धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहीं और वर्तमान तक आते–आते उन्होंने समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जगह बना ली है। उनके सशक्तीकरण में दशकों लग गए, लेकिन अब महिलाएं समाज में अपना मुकाम बनाने में सफल हो रही हैं। भारतीय महिलाओं में ईमानदारी और उत्साह के साथ कार्य करने की क्षमता, दूरदर्शिता, जीवंतता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुण प्राकृतिक रूप से उनके स्वभाव में निहित रहते हैं। वे सभी चुनौतियों का सामना अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा के द्वारा आसानी से कर लेती हैं। आज भारतीय महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे जितनी कुशलता के साथ घर–परिवार संभाल सकती हैं, उतनी ही कुशलता से हर क्षेत्र में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकती हैं। महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता सहज रूप से विद्यमान होती है। भारत अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है, ऐसे में अगर वो अपनी आधी आबादी के सशक्तीकरण व विकास पर ध्यान नहीं देगा तो सफलता उससे कोसों दूर रहेगी। इसीलिए अब लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए, लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां संभालने के

सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए, लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां संभालने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। महिलाएं समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि भारत की महिलाएं अपनी कार्यक्षमता व दृढ़ इच्छाशक्ति से देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में कामयाब होंगी।

अवसर प्राप्त हो रहे हैं। महिलाएं समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि भारत की महिलाएं अपनी कार्यक्षमता व दृढ़ इच्छाशक्ति से देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में कामयाब होंगी।

जहां आधी आबादी को उनके अधिकार नहीं मिलते, उन्हें दबाया या कुचला जाता है, वो देश या समाज कभी विकास नहीं कर पाता। कोई देश तभी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है, जब उसके समाज में लैंगिक समानता हो। अर्थात समाज में महिलाओं तथा पुरुषों को समान रूप से दायित्व, अधिकार और रोज़गार प्राप्त हों। समाज में भेदभाव की स्थितियां देश व समाज के विकास में बाधा पहुंचाती हैं। भारत की महिलाएं वर्षों से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती रही हैं। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, किंतु आज भी उन्हें कई पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी कुछ समाज महिलाओं को पर्दे में रखने के पक्षधर हैं। बहुत सी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते। उनका छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है और उन्हें घर गृहस्थी के बोझ तले दबने को मजबूर कर दिया जाता है। कम उम्र में ही मां बन जाने के कारण वे कई रोगों का शिकार हो जाती हैं और कभी–कभी इस कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया जाता है और उनके व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर नहीं मिल पाता। कई घरों में महिलाओं को घर से बाहर निकल कर नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती और यदि वे नौकरी करती भी हैं तो उन पर घर और ऑफिस का इतना अधिक बोझ बढ़ जाता है कि मजबूर होकर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है, अर्थात घर के सदस्य घरेलू कामों में उनका हाथ भी नहीं बंटाते। जो महिलाएं घरों में खाना बनाने, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने आदि का काम करके आजीविका प्राप्त करती हैं, उन्हें भी उनकी मेहनत के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं हो पाता। गृहिणियों के कामों को अवैतनिक माना जाता है और उन्हें अपने खर्चे के लिए पति या घर के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।

महिलाओं की तस्करी, घरेलू हिंसा तथा यौन शोषण को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो सका। शायद इसका कारण यह भी है कि महिलाएं कुछ पारिवारिक–सामाजिक विवशताओं के चलते इन कानूनों का उपयोग करने में असमर्थ होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं या फिर उनसे हारकर अपनी जान दे देती हैं। हालांकि देश की महिलाएं अब कला, खेल, विज्ञान, तकनीक और रक्षा क्षेत्र जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो महिलाएं खेती किसानी के कामों में, मिल और फैक्ट्रियों में बतौर श्रमिक पुरुषों के समान काम करती हैं, उनका पारिश्रमिक पुरुषों से कम होता है। यह भेदभाव अत्यंत चिंताजनक है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

भारत के संविधान के अनुसार देश में काम करने वाला प्रत्येक नागरिक बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान वेतन पाने का अधिकारी है, तो फिर महिलाओं को उनके हक से वंचित क्यों रखा जाता है? आज 21वीं सदी के पढ़े –लिखे समाज में भी महिलाओं को लेकर पुरुषों के नज़रिए में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। महिलाओं को परेशान करने का एक नया माध्यम अब सोशल मीडिया भी बन चुका है, जहां अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेजों द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान के साथ एक हिंसा मुक्त समाज में जीने के लिए उनकी सामाजिक व कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए सामाजिक सहयोग भी बहुत अपेक्षित है, क्योंकि जब तक हमारा समाज महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक नहीं होगा, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाता है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकती हैं, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। शिक्षित महिलाएं बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है। शिक्षा महिलाओं को सामाजिक मुद्दों के बारे में

जागरूक करती है और उन्हें समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करती है, जिससे वे समुदायों और देश का नेतृत्व कर सकती हैं। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब परिवारों में लड़कियों की शिक्षा दर अभी भी कम है। लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियां भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हमें लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा एक अनिवार्य उपकरण है। इसलिए सभी महिलाओं को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, या सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत को एक अधिक समृद्ध और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।

सरकार की ओर से महिलाओं की हिंसा तथा यौन शोषण को रोकने और उनके विकास के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। वित्तपोषण सेवाओं के साथ–साथ महिलाओं की दक्षता और रोजगार कार्यक्रम देश की ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। यौन शोषण, घरेलू हिंसा और असमान

पारिश्रमिक से संबंधित कानूनों को मजबूती दी जा रही है। इसके अलावा सरकार का 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान भी सफल होता दिख रहा है।

आज बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक तथा राजनीति से लेकर रक्षा क्षेत्र तक में वे अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपनी सशक्त भूमिका हर क्षेत्र में बखूबी निभा रही हैं। अब वह केवल घर की चहारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि बाहर निकल कर वो अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा परिवार, समाज व देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हो रहा है, लेकिन लिंग भेद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस ओर मजबूती से कदम बढ़ाने की जरूरत है। जब तक महिलाओं को बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। इसलिए सरकार, नीति निर्माताओं व पूरे समाज को महिलाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा करनी होगी और हर क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान करने होंगे, तभी हम नए युग में भेदभाव रहित एक नए समाज का गठन करने में सक्षम हो पाएंगे।

महिला सशक्तीकरण से सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, और घरेलू हिंसा में कमी आती है। महिलाएं शिक्षित और सशक्त होने पर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, जिससे समग्र सामाजिक विकास होता है। महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यदि उन्हें रोज़गार के समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो वे अपनी आय से परिवार का भरण–पोषण कर सकती हैं और देश की जीडीपी में भी वृद्धि कर सकती हैं। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है।

जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो नीतियां अधिक समावेशी और न्यायसंगत होती हैं। महिला सशक्तीकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के विकास का मुद्दा है। इसलिए महिला सशक्तीकरण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हमें लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें महिलाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यदि हम भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। यह केवल सरकार या निजी क्षेत्र का ही दायित्व नहीं है, बल्कि यह हम सबका भी दायित्व है। ◆

मो. : 9336111418

उ.प्र.
रेरा

'रेरा है तो भरोसा है'

होम बायर्स के लिए सावधानियाँ

- विज्ञापन में परियोजना की रेरा पंजीकरण संख्या तथा उ.प्र. रेरा पोर्टल न अंकित हों तो ऐसी परियोजना में बुकिंग न करें और ऐसे प्रोमोटर अथवा एजेण्ट के साथ कोई लेन-देन न करें।
- उ.प्र. रेरा वेब पोर्टल https://www.up-rera.in/projects पर परियोजना की पंजीयन संख्या तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करें।
- किसी भी एजेण्ट के माध्यम से बुकिंग से पहले एजेण्ट के पंजीकरण संख्या की जाँच उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर कर लें।
- परियोजना का भू-क्षेत्र 500 वर्ग मी. से अधिक होने अथवा उसमें आठ से अधिक अपार्टमेन्ट होने पर रेरा में पंजीकरण बिना प्रोमोटर अथवा एजेण्ट द्वारा किसी प्रकार का विज्ञापन, बुकिंग, विक्रय इत्यादि प्रतिबन्धित है। इसका विशेष ध्यान रखें।
- प्रोमोटर अथवा एजेण्ट के लुभावने ऑफर्स से प्रभावित होकर जल्दबाजी में बुकिंग अथवा निवेश न करें। ऐसा निर्णय जोखिम भरा हो सकता है।

रियल इस्टेट एजेण्ट के कार्य तथा दायित्व

- उ.प्र. रेरा में पंजीकरण कराने के पश्चात् तथा प्रोमोटर द्वारा प्रचार-प्रसार, बुकिंग, इत्यादि के लिए प्राधिकृत किए जाने के उपरान्त ही कार्य करें।
- प्रोमोटर द्वारा प्रमाणित विज्ञापन सामग्री का ही उपयोग करें।
- परियोजनाओं का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार करते समय परियोजना की रेरा पंजीयन संख्या, उ.प्र. रेरा पोर्टल तथा एजेण्ट पंजीयन संख्या का प्रमुखता से उल्लेख करें।
- आवंटी को समस्त जानकारियां ठीक प्रकार से दें।
- फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए पेज पर परियोजना के प्रचार-प्रसार के क्रिएटिव या विवरण में अपनी एजेण्टशिप का पूरा नाम तथा पंजीकरण संख्या, परियोजना की पंजीकरण संख्या और उ.प्र. रेरा वेबसाइट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।
- भ्रामक, अस्पष्ट सुविधाओं एवं विशिष्टियों का प्रचार-प्रसार न करें।
- किसी ऐसी सेवा का आश्वासन न दें, जिसका दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

अधिक जानकारी की लिए विजिट करें - https://www.up-rera.in
हेल्पलाइन नं.- +91 9151602229 (लखनऊ), +91 9151672229 (एन.सी.आर.)

फॉलो एवं सब्सक्राइब करें : UPRERAOfficial

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय : नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007
एन.सी.आर. कार्यालय : एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201310

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 से डेयरी उद्यम को प्रोत्साहन

पूंजीगत अनुदान

नवीन व विस्तारित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई को ₹5 करोड़ तक का अनुदान

ब्याज उपादान

देय ब्याज दर के 5% का 5 वर्षों हेतु ₹1 से 10 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति

- नवीन व विस्तारित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई
- दुग्धशाला के अंदर तकनीकी उन्नयन व बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी
- नवीन व विस्तारित पशु आहार इकाई
- कोल्ड चेन की स्थापना
- मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद इकाई

बाजार विकास एवं ब्रांड प्रोत्साहन प्राविधान

परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25%, जो ₹20 लाख व Freight on Board मूल्य का 20%, अधिकतम ₹40 लाख

मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान

टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50%, अधिकतम ₹5 लाख अनुदान

पेटेण्ट डिजाइन पंजीकरण प्राविधान

फीस का 75%, अधिकतम ₹5 लाख अनुदान

विद्युत शुल्क

10 वर्ष की अवधि में भुगतान किए गए विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति

स्टाम्प शुल्क

शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति

अधिक जानकारी/गाइडलाइन के लिए विभागीय वेबसाइट पर जाएं - updairydevelopment.gov.in या जनपदीय उप दुग्धशाला विकास अधिकारी से संपर्क करें।

दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए शिशिर, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित।